प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
10.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18.00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से नई दिल्ली के तीन दिवसीय दौरे पर है। उनका विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेशहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा कर वित्तीय मदद का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भेंट कर संगठन से जुड़े मुद्दो पर भी चर्चा कर सकते हैं।

एमओयू

प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन करेगा और इसके लिए दो बड़े संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति महावीर सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है जो सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए नॉर्वे और इटली के दो बड़े संस्थानों के साथ समझौता किया गया है।

शांडिल

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं समाज को सशक्त बनाने का एक माध्यम है और राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन में आज ज़िला कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने बताया कि ज़िले में सामाजिक सुरक्षा पैंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर इस वित्त वर्ष के दौरान 94 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। धनीराम शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सोलन ज़िले में 18 हज़ार से अधिक महिलाओं को हर महीने 15 सौ रूपये की राशि दी जा रही है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांगड़ा ज़िले के नूरपुर में भाजपा की विभिन्न राज्य इकाईयों द्वारा भेजी गई राहत सामग्री को चंबा ज़िले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में देशभर से भाजपा कार्यकर्ता राहत सामग्री भेज रहे हैं और पार्टी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार को राजनीति के बजाए राहत कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं अस्थाई रूप से बहाल की गई हैं जिन्हें जल्दी ही स्थाई तौर पर बहाल करने की जरूरत है।